

## भारत में नविश संवर्द्धन

### प्रलिस के लयः

प्रत्यक्ष वदशी नवऱश, आत्मनरऱभर अभयऱन, इनसॉलवेंसी ँड बैकरप्सी कोड, ईज़ ऑफ डूङ्ग बज़ऱनेस रैंकऱगऱ, नेशनल इंफ़रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट फंड, इनवेस्ट इंडयऱ

### मेन्स के लयः

भारत में नवऱश संबंघी मुददे और उसके संवर्द्धन हेतु उठाए गए कदम

## चर्चा में क्यों?

हल ही में अमेरऱकी वदऱश वऱभऱग ने '2021 इनवेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स: इंडयऱ' (2021 Investment Climate Statements: India) शीर्षक से ँक रऱपॉरट जऱरी की । रऱपॉरट में आर्थऱक मंदी और कोवडऱ-19 महऱमऱरी के मददेनज़र भारत सरकऱर दवऱरऱ कयऱ गए संरचनऱत्मक आर्थऱक सुधऱरों की सरऱहनऱ की गई है ।

- हलॉक रऱपॉरट में कऱहऱ गयऱ है कऱ भारत वयऱपऱर करने के लयऱ ँक चुनौतीपूर्ण स्थऱन बनऱ हुऱ है ।
- इससे पहले यूके इंडयऱ बज़ऱनेस कऱउंसलऱ (UKIBC) ने ज़ोर देकर कऱहऱ थऱ कऱ आत्मनरऱभर भारत कऱर्यकऱरम के तहत कुछ सुधऱरों के परऱगऱम यूके और सऱभी बहुरऱषट्ररीय कंपनयऱों के लयऱ नकऱरऱत्मक हो सकते हैं ।

## प्रमुख बऱदुः

- नज़ीकरणः फरवरी 2021 में भारत सरकऱर ने ँक [महतत्वाकऱंक्षी नज़ीकरण कऱर्यकऱरम](#) के मऱध्यम से 2.4 बलऱयऱन डॉलर जुटऱने की योजनऱ की घोषणऱ की, जो अर्थव्यवस्था में सरकऱर की भूमऱकऱ को नऱटकीय रूप से कम कर देगी ।
- हल के आर्थऱक सुधऱरः
- प्रत्यक्ष वदशी नवऱश (FDI) उदऱरीकरणः अगस्त 2019 में सरकऱर ने उदऱरीकरण उऱपऱयों के ँक नए पैकेज की घोषणऱ की और कोयलऱ खनन तथऱ अनुबंध नरऱमऱण सहऱतऱ कई कषेत्ऱरों को [सवचऱलऱतऱ मऱरु](#) के तहत लऱयऱ गयऱ ।
  - मऱर्च 2021 में संसद ने भारत के बीमऱ कषेत्ऱर को और उदऱर बनऱयऱ तथऱ [प्रत्यक्ष वदशी नवऱश \(FDI\) की सीमऱ को 49% से बढऱकर 74% कर दयऱ](#) ।
- आत्मनरऱभर भारत अभयऱनः कोवडऱ-19 से संबंघऱतऱ आर्थऱक मंदी कऱ मुकऱबलऱ करने के लयऱ भारत सरकऱर ने [आत्मनरऱभर भारत अभयऱन](#) शुरु कयऱ ।
  - इस कऱर्यकऱरम में वयऱपक सऱमऱजकऱ कल्यऱण और आर्थऱक प्रोत्सऱहन कऱर्यकऱरमों तथऱ बुनयऱदी ढऱँचे ँवं सऱरवजनकऱ स्वऱस्थ्य पर खरच में वृद्धऱ की परकऱल्पनऱ की गई है ।
  - इसके अलऱवऱ इसकऱ उददेश्य वैश्वकऱ बऱज़ऱर में हसऱसेदऱरी हऱसलऱ करने के लयऱ सुरकषऱ अनुऱपऱलन और सऱमऱनों की गुणवत्तऱ में सुधऱर करते हुए प्रतऱसऱथऱपन पर धयऱन केंद्रऱतऱ करऱ आयऱत नरऱभरतऱ को कम करनऱ है ।
- उतऱपऱदन लकऱड प्रोत्सऱहन योजनऱः सरकऱर ने फऱरमऱसयूटकऱल्स, ऑटोमोबऱइल, टेकसऱटऱइल, इलेक्ट्रॉनऱकऱस और अन्य कषेत्ऱरों में वनऱरऱमऱण को बढऱवऱ देने के लयऱ [उतऱपऱदन से जुडे प्रोत्सऱहनों](#) को भी अऱपनऱयऱ ।
- इनसॉलवेंसी ँड बैकरप्सी कोडः वरष 2016 में [इनसॉलवेंसी ँड बैकरप्सी कोड](#) (IBC) की शुरुऱत और कऱर्यऱनव्यन ने इनसॉलवेंसी संबंघऱतऱ मौजूदऱ ढऱँचे को बदल दयऱ तथऱ अधऱकऱ आवश्यक सुधऱरों कऱ मऱरु प्रशस्त कयऱ ।
  - पछऱले तीन वरषों में जऱनऱ कषेत्ऱरों में भारत ने [वशऱव बैक की ईज ऑफ डूङ्ग बज़ऱनेस रैंकऱगऱ](#) में सऱबसे अधऱकऱ सुधऱर कयऱ है, वऱह रज़ऱलवऱगऱ इनसॉलवेंसी मेटऱरऱकऱ के तहत रऱहऱ है ।
- मध्यस्थतऱ के वैश्वकऱ मऱनऱकों कऱ मऱलऱनः भारत सरकऱर ने [मध्यस्थतऱ और सुलह \(संशोधन\) अधनऱयऱम, 2021](#) पऱरऱतऱ कयऱ ।
  - अधनऱयऱम में घरेलू और अंतरऱरऱषट्ररीय मध्यस्थतऱ के लयऱ प्रऱवधऱन तथऱ सुलह की कऱर्यवऱही संचऱलऱतऱ करने हेतु कऱनून को परऱषऱतऱ कयऱ गयऱ है ।
- सॉवरेन वेलथ फंडः वरष 2016 में भारत सरकऱर ने [नेशनल इंफ़रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट फंड](#) (NIIF) की स्थापनऱ की, जऱसऱ इंफ़रास्ट्रक्चर सेक्टऱर में नवऱश को बढऱवऱ देने के लयऱ भारत कऱ पहलऱ सॉवरेन वेलथ फंड मऱनऱ जऱतऱ है ।

- सरकार ने फंड में 3 अरब डॉलर का योगदान देने पर सहमति जताई, जबकि अतिरिक्त 3 अरब डॉलर नज्दी क्षेत्र से जुटाए जाएंगे।
- **श्रम संहिता:** बजट 2021 में सरकार ने घोषणा की कि अप्रैल, 2021 से भारत में [चार श्रम संहिताओं](#) को लागू किया जाएगा।
  - इन श्रम संहिताओं में देश के पुरातन श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमिकों के लाभों से समझौता किये बिना आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की परिकल्पना की गई है।
- **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार के लिये अनन्य उपाय:**
  - **इनवेस्ट इंडिया:** यह आधिकारिक निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है, जो निवेशकों के साथ उनके निवेश जीवनचक्र के माध्यम से बाज़ार प्रवेश रणनीतियों, उद्योग विश्लेषण, भागीदारी खोज और आवश्यकता के अनुसार नीतिकी वकालत करने के साथ-साथ सहायता प्रदान करने के लिये काम करती है।
  - **प्रगति पहल:** विशेष रूप से प्रमुख परियोजनाओं के मामले में अनुमोदन प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने [सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन \(PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation\)](#) पहल शुरू की।
    - यह सरकार की अनुमोदन प्रक्रिया को गति देने के लिये एक डिजिटल, बहु-उद्देश्यीय मंच है।

### वैदेशी निवेशकों के लिये चरितीय आर्थिक नीतियाँ:

- विवादास्पद नरिणय: हाल ही में सरकार ने दो विवादास्पद नरिणय लिये अर्थात् [जम्मू और कश्मीर राज्य \(J&K\) से विशेष संवैधानिक दर्जा हटाना](#) तथा [नागरिकता संशोधन अधिनियम \(CAA\), 2019](#) पारित करना।
  - हालाँकि भारत का कहना है कि CAA और अनुच्छेद 370 को समाप्त करना उसका आंतरिक मामला था तथा "किसी भी वैदेशी पार्टी को भारत की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को उठाने का कोई अधिकार नहीं है।"
- नए संरक्षणवादी उपाय: अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों ने वैदेशी पूंजी के साथ-साथ प्रबंधन और नियंत्रण प्रतबंधों के लिये इक्विटी सीमाएँ बरकरार रखी हैं, जो निवेश को अवरुद्ध करते हैं।
  - उदाहरण : वर्ष 2016 में भारत ने [घरेलू एयरलाइनों में 100% तक एफडीआई](#) की अनुमति दी थी, लेकिन पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण (SOEC) नियमों का मुद्दा, जो कि भारतीय नागरिकों द्वारा बहुमत नियंत्रण को अनिवार्य करता है, को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।
- द्विपक्षीय निवेश समझौते और कराधान संधियाँ : भारत ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही में निवेश परिस्थितियों के अनुकूल नरिणयों के पश्चात् दिसंबर 2015 में एक नए मॉडल [द्विपक्षीय निवेश संधि \(Bilateral Investment Treaty-BIT\)](#) को अपनाया।
  - नया मॉडल बीआईटी वैदेशी निवेशकों को निवेशक-राज्य विवाद नपिटान विधियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है और इसके बजाय वैदेशी निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में भाग लेने से पूर्व सभी स्थानीय न्यायिक एवं प्रशासनिक उपायों को समाप्त करने की आवश्यकता होती है।
- खरीद नियम शामिल हैं जो प्रतस्पर्द्धी वकिलों को सीमित करते हैं: [सरकारी खरीद के लिये प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस \(PMA\)](#) ने भारत में कार्यरत वैदेशी फर्मों के लिये काफी चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।
  - राज्य के स्वामित्व वाले "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम" और सरकार द्वारा 50% से अधिक स्थानीय सामग्री का उपयोग करने वाले वकिरेताओं को 20% मूल्य वरीयता दी जाती है।
- बौद्धिक संपदा अधिकार: कमज़ोर बौद्धिक संपदा (IP) के संरक्षण और प्रवर्तन को लेकर चर्चाओं के कारण भारत को वर्ष [2020 की स्पेशल 301 नामक रिपोर्ट में प्राथमिकता नगिरानी सूची \(PWL\)](#) में रखा गया।
- भ्रष्टाचार: [ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक \(CPI\) 2020](#) में भारत 40 अंकों के साथ 180 देशों में 86वें स्थान पर है।
- **अन्य मुद्दे:** ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो द्विपक्षीय व्यापार में वसितार को प्रतबंधित करते हैं जैसे- स्वच्छता और पादप स्वच्छता (Phytosanitary) मानक एवं भारतीय-वशिष्ट मानक, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

### आगे की राह

- भारत सरकार को निवेश और व्यवसायों के लिये नौकरशाही बाधाओं को कम करके एक आकर्षक एवं विश्वसनीय निवेश वातावरण को बढ़ावा देना चाहिये।
- भारत और अन्य देशों की सरकारों को मानकों, व्यापार सुविधा, प्रतस्पर्द्धी एवं डंपिंग रोधी जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिये।

### स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस